Submitting of Report of NDC Committee

780. SHRIMATI ILA PANDA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the NDC Committee on power has submitted its report and if so, what are its main recommendations; and

(b) if not, by when it is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) The work of the NDC Committee on Power is in progress, as such it is not possible to indicate a date for submission of the Report.

बिहार राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन

781. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के माध्यम से बिहार राज्य द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) बिहार की राज्य योजना स्कीमों के कार्यान्वयन तथा अलग-अलग स्कीमों के कार्यान्वयन का अध्ययन किया गया है। इनमें से कुछ ने स्कीमों के प्रबंधन तथा निचले स्तर के चुनींदा निकायों की सक्रियता में प्रभावी विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता दर्शाई है।

(ग) और (घ) सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को अध्ययनों के अभिमतों से अवगत करा दिया गया है।

Annual Plans Approved for various States

782. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether discussion with the States in regard to the annual plan for 1994-95 have been completed; and

(b) if so, what are the details of the plans approved for various States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHIR GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) A Statement indicating agreed outlays of all the States for the Annual Plan 1994-95 is attached.

Statement

Annual Plan 1994-95 Agreed Outlays States

(Rs. Crores)

Sl. No.	States	Agreed Outlay
1.	Andhra Pradesh	2130.00
2.	Arunachal Pradesh	335.00
3.	Assam	1051.00
4.	Bihar	2400.00
5.	Goa	182.00
6.	Gujarat	2240.00
7.	Haryana	1025.00
8.	Himachal Pradesh	650.00
9.	Jammu & Kashmir	950.00
10.	Karnataka	3275.00
11.	Kerala	1260.00
12.	Madhya Pradesh	2750.00
13.	Maharashtra	4400.00
14.	Manipur	240.00
15.	Meghalaya	281.00
16.	Mizoram	207.66
17.	Nagaland	220.00
18.	Orissa	1950.00
19.	Punjab	1450.00
20.	Rajasthan	2450.00
21.	Sikkim	135.00

1. 2	3
22. Tamil Nadu	2750.00
23. Tripura	310.00
24. Uttar Pradesh	4562.00
25. West Bengal	1706.00

Allocation of Funds for Railways Development

783. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the railways have requested the Planning Commission for increase of allocation for their expansion programme as well as for their annual plan;

(b) if so, the amount approved by the Planning Commission in this regard; and

(c) what are the reasons for not allocating adequate funds for the development of the railways?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHIR GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) As against an Outlay of Rs. 6900 crores in 1993-94 in the railways sector, the Planning Commission approved an Outlay of Rs. 7149 crores for their Annual Plan 1994-95 after taking into consideration the requirements, the railways capacity to raise funds by way of internal resources and market borrowings, and the overall budgetary resources available.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय परियोजनाओं की समीक्षा

784. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीस करोड़ या इससे अधिक की लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की समीक्षा कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार कमी पाई गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जी हां। दिनांक 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार सरकार ने 20 करोड़ रु० और उसके अधिक लागत वाली 367 परियोजनाओं की समीक्षा की है।

(ख) इन 367 परियोजनाओं में से 177 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही थीं और 158 परियोजनाओं की लागत में, उनके नवीनतम अनुमोदित समय और लागत के संदर्भ में, सामान्यतः भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, निधियों की कमी, निकृष्ट परियोजना प्रबंध, ठेकेदारों की असफलता, उपकरणों की आपूर्ति में विलंब तथा अन्य कठिनाइयों के कारण वृद्धि हुई है।

(ग) परियोजनाओं को कार्यान्वयन के समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यान्वयन में कमियों से बचने के लिए सरकार द्वारा सामान्य रूप से उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

— कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मासिक/तिमाही प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से परियोजनाओं का गहन प्रबोधन।

— प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की गई प्रगति की विस्तृत आवधिक समीक्षा तथा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु परियोजना प्राधिकरणों पर लगातार दबाव डालना।

— ठेका पैकेजों को त्वरित गति से अंतिम रूप